1984 के पश्चात् की अवधि इस बात की पुष्टि करती है कि कुछ मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण और चार एककों को बन्द करने के निर्णय आदि का वर्तमान कर्मचारिवृंद पर प्रभाव पड़ा है। यद्यपि, चार एककों को बन्द करने के निर्णय के कारण सीधी भर्ती पर प्रतिबन्ध है, फिर भी अनिवार्य पदों को भरने की अनुमति दी गई है।

(ग) मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण के कारण उत्पादन में वास्तव में वृद्धि हुई है। उत्पादन हानि के लिए मात्र विद्यमान रिक्तियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। बजट प्रावधान, कागज, पादर तथा प्रशिक्षित जनशक्ति की अनुपलब्धता भी इसके कारक हैं।

अम्बेडकर आवास योजना

2668. **श्रीमती सत्या बहिन:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिन्न-भिन्न श्रेणियों के मकानों के लिए अम्बेडकर आवास योजना के अधीन पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) इस योजना के अधीन विभिन्न श्रेणियों के मकानों का आवंटन कब तक कर दिए जाने की सम्भावना है और इससे श्रेणीवार कितने व्यक्तियों को लाभ हो जाने की संभावना है ; और

(ग) मकानों के आवंटन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग के लिए 10,000 व्यक्ति और जनता वर्ग के फ्लैटों के लिए 3000 व्यक्ति पहले ही पंजीकृत हैं। मध्यम आय वर्ग के फलैटों के लिए 7000 व्यक्तियों को अभी पंजीकृत किया जाना है।

(ख) और (ग) इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत/पंजीकृत किए जाने वाले सभी 20,000 व्यक्तियों को 1994–95 तक फ्लैट आवंटित किए जाने की आशा है।

Sulabh Sauchalayas

2669. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Sulabh Sauchalayas have provided an alternative to scavenging in the country;

(b) if so, whether Government have any proposal to provide the facility throughout the country;

(c) if so, what are the details of plans in this regard;

(d) whether Government have decided to provide the facility in various parts of Madhya Pradesh; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Since sanitation is a State subject, it is the responsibility of the State Governments and urban local bodies to provide proper sanitation facilities. The Government of India has since launched the scheme of low cost sanitation and liberation of scavengers for the eradication of manual scavenging in the country. The scheme envisages conversion of dry laterines/construction of new water seal pour flush laterines on 'whole town' basis. It is being operated through the Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) by providing a mix of subsidy from the Central Government and loans from HUDCO in a synchronised manner to the State Governments for implementation of the programme.

(d) and (e) Proposals in respect of 57 towns in Madhya Pradesh have been approved for implementation under the above scheme.